भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4230

दिनांक 20.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

आईएमईसी परियोजना से संबंधित चुनौतियां

4230. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गाजा की मौजूदा स्थिति के संबंध में आईएमईसी परियोजना से संबंधित किसी चुनौती का सामना करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आईएमईसी परियोजना की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) से (ग) नई दिल्ली में जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के अवसर पर, भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका के नेताओं ने 9 सितंबर 2023 को एक समझौता ज्ञापन की घोषणा की, जिसमें एक नया भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) विकसित करने हेतु मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई गई। आईएमईसी में दो अलग-अलग गलियारे शामिल होंगे, पूर्वी गलियारा भारत को खाड़ी से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। इस गलियारे का उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना, दक्षता बढ़ाना, लागत कम करना, क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना, व्यापार पहुंच बढ़ाना, रोजगार सृजन करना और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करना है, जिसके परिणामस्वरूप एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व का परिवर्तनकारी एकीकरण होगा।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) के संचालन के लिए सहयोग से संबंधित एक अंतर-सरकारी रूपरेखा करार (आईजीएफए) पर 13 फरवरी 2024 को हस्ताक्षर किए गए। इस रूपरेखा के मुख्य तत्वों में एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र सहित एक संभारतंत्रीय मंच का विकास और प्रबंधन, और आईएमईसी को सक्षम करने के लिए सभी प्रकार के सामान्य कार्गो, थोक, कंटेनर और तरल थोक को संभालने के लिए आपूर्ति श्रृंखला सेवाओं का प्रावधान शामिल है।

आईएमईसी के कार्यान्वयन में अनेक हितधारक शामिल हैं और यह अभी प्रारंभिक चरण में है।